



भारत के राजकोषीय संघवाद पर पुनर्विचार

यह एडिटरियल 26/08/2023 को 'द हट्टू' में प्रकाशित [“Rethink the emerging dynamics of India's fiscal federalism”](#) लेख पर आधारित है। इसमें भारत के राजकोषीय संघवाद पर पुनर्विचार की आवश्यकता के बारे में चर्चा की गई है।

प्रलिस के लिये:

[73वाँ और 74वाँ संविधान संशोधन](#), [योजना आयोग](#), [नीतिआयोग](#), [राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन \(FRBM\) अधिनियम 2003](#), [महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005](#), [बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009](#), [राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013](#), [GST क्षतपूरत उपकर](#), [अनुच्छेद 246](#) और [सातवीं अनुसूची](#), [ऑफ-बजट उधार](#), [मानव विकास सूचकांक \(HDI\)](#)।

मेन्स के लिये:

राजकोषीय संघवाद: उन उपायों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है जिनके माध्यम से भारत अपने राजकोषीय संघवाद को मज़बूत कर सकता है।

भारतीय संविधान को एक 'होल्डिंग टूगेदर फेडरेशन' (holding together federation) के रूप में समझा जा सकता है जो एकजुटता (unity) की ओर कुछ झुकाव रखता है। यह व्यवस्था उन कारकों को संबोधित करने के लिये अपनाई गई जो स्वतंत्रता से पहले देश के लिये वखिंडनकारी थे। पछिले 73 वर्षों में यह अत्यंत सुदृढ़ और अनुकूलनीय सदिध हुआ है। हालाँकि, वर्तमान समय में इस पर पुनर्विचार करना आवश्यक हो गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच धन एवं संसाधनों को किस प्रकार साझा किया जाए। ऐसा इसलिये है क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था बदल रही है और उसकी आवश्यकताएँ अब अलग हैं।

राजकोषीय संघवाद:

- **राजकोषीय संघवाद (Fiscal federalism)** पद यह प्रकट करता है कि किसी देश में सरकार के वभिन्न स्तरों के बीच वत्तीय शक्तियों और उत्तरदायित्वों को कैसे वभिजति किया जाता है।
- इसमें इस तरह के प्रश्न शामिल हैं कि केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा कौन-से कार्य एवं सेवाएँ प्रदान की जानी चाहिये, राजस्व कैसे बढ़ाया जाना चाहिये एवं उनकी साझेदारी कैसे की जाए और दक्षता एवं समता सुनिश्चित करने के लिये हस्तांतरण या अनुदान कैसे आवंटित किया जाए।

राजकोषीय संघवाद की स्थापना के लिये प्रमुख उपाय:

- **कराधान और व्यय शक्तियों की संवैधानिक व्यवस्था:** संविधान सरकार के वभिन्न स्तरों के लिये कराधान और व्यय की शक्तियों एवं कार्यों को परिभाषित करता है, जहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच स्पष्ट सीमांकन किया गया है।
- **वत्त आयोग: वत्त आयोग (Finance Commission- FC)** एक संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 280) है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच कर राजस्व के वत्तरण की अनुशंसा करने के लिये उत्तरदायी है। यह राज्यों के वत्तीय संसाधनों को बढ़ाने, राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा देने और राजकोषीय मामलों में स्थिरता सुनिश्चित करने के उपाय भी सुझाता है।
- **वस्तु एवं सेवा कर: वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax- GST)** एक व्यापक अपरत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं पर वभिन्न केंद्रीय एवं राज्य करों को प्रतस्थापित करता है। इसका प्रशासन जीएसटी परिषद (GST Council) द्वारा किया जाता है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
- **सहायता अनुदान प्रणाली: सहायता अनुदान प्रणाली (Grants-in-Aid System)** (अनुच्छेद 275) में वशिष्ट उद्देश्यों या योजनाओं के लिये केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को धन का वविकाधीन हस्तांतरण शामिल है। इन अनुदानों का उद्देश्य राज्यों के संसाधनों को पूरकता प्रदान करना और क्षेत्रीय असमानताओं एवं विकास संबंधी अंतरालों को संबोधित करना है।

भारत के राजकोषीय संघवाद पर पुनर्विचार की आवश्यकता क्यों है?

- **नयोजित अर्थव्यवस्था से बाज़ार-मध्यस्थता प्रणाली की ओर संक्रमण:** एक नयोजित अर्थव्यवस्था (Planned Economy) से बाज़ार-मध्यस्थ प्रणाली (Market-Mediated System) की ओर संक्रमण ने केंद्रीकृत नरिणयन से अधिक वकिेंद्रीकृत दृष्टिकोण

की ओर आगे बढ़ने को दर्ज़ क़िया है जहाँ बाज़ार की शक्तियों अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस परिवर्तन का संसाधन आवंटन, नविश और समग्र आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ा है। इससे राज्यों को आर्थिक नरिणयन के मामले में अधिक स्वायत्तता प्राप्त हुई है।

■ **73वाँ और 74वाँ संवैधानिक संशोधन:** भारत में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासी नकियाँ के रूप में पंचायतों और नगर नकियाँ की स्थापना हुई। इस वकिंदरीकरण का उद्देश्य स्थानीय शासन को बढ़ाना, ज़मीनी स्तर के संस्थानों को सशक्त बनाना और विकास नीतियों का अधिक प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना था।

- हालाँकि इन संशोधनों ने राज्य सरकारों से स्थानीय नकियों को धन का पर्याप्त और पूर्वानुमानित हस्तांतरण सुनिश्चित नहीं क़िया है।
- राज्य सरकारें प्रायः स्थानीय नकियों के लिये सहायता अनुदान पर रोक या वलिबन के लिये अपनी वविकाधीन शक्तिका उपयोग करती हैं, जिससे उनकी ववित्तीय स्वायत्तता और जवाबदेही प्रभावित होती है।

■ **योजना आयोग को समाप्त करना और नीति आयोग की स्थापना:** वर्ष 2015 में योजना आयोग को **नीति आयोग (National Institution for Transforming India- NITI Aayog)** से परतस्थापित कर द़िया गया। यह परिवर्तन टॉप-डाउन नयिोजन दृष्टिकोण से अधिक सहयोगात्मक एवं लचीले नीति-नरिमाण प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ने का परतनिधित्व करता है। नीति आयोग को सहकारी संघवाद (cooperative federalism) को बढ़ावा देते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को रणनीतिक एवं तकनीकी सलाह प्रदान करने की भूमिका सौंपी गई है।

- योजना आयोग के वपिरीत, नीति आयोग का केंद्र-राज्य हस्तांतरण में कोई दखल नहीं है, जो राज्यों को योजना अनुदान के साथ सुधार की ओर आगे बढ़ने के लिये प्रेरित कर सकता।

■ **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003:** राजकोषीय घाटे को कम करने और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करने के माध्यम से राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिये FRBM अधिनियम पेश क़िया गया था। यह अधिनियम केंद्र और राज्य दोनों सरकारों पर लागू होता है, जिससे एक अधिक उत्तरदायी राजकोषीय दृष्टिकोण को बढ़ावा मलित है। हालाँकि, इसके कार्यान्वयन से कभी-कभी राजकोषीय वविक के साथ विकास-उन्मुख वयय को संतुलित करने की चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।

■ **वस्तु एवं सेवा कर (GST) अधिनियम और जीएसटी परषिद:** वर्ष 2017 में लाया गया जीएसटी अधिनियम एक महत्त्वपूर्ण कर सुधार (tax reform) को चहिनित करता है। इसने अप्रत्यक्ष करों के जटिल जाल को एक एकीकृत कर ढाँचे से परतस्थापित क़िया, कारोबार सुगमता (ease of doing business) को बढ़ावा द़िया और 'टैक्स कैस्केडिंग' (tax cascading) को कम क़िया। जीएसटी लागू होने से राज्यों की कर संग्रह शक्तियाँ कम हो गईं।

- कुछ राज्यों के ववित्त मंत्रियों ने आरोप लगाया है कि **जीएसटी परषिद** के नरिणय राजनीतिक ववचारों से प्रभावित होते हैं, न कि आर्थिक तर्कसंगतता से।
- उनकी यह भी शक़ायत रही है कि उनके ववचारों को अधिक महत्त्व नहीं द़िया जाता और बहुमत से उनके ववचारों को दबा द़िया जाता है।

■ **उपकर और अधभार का उपयोग:** वशिषिट उद्देश्यों के लिये राजस्व जुटाने हेतु उपकर (cess) और अधभार (surcharge) का उपयोग एक आम स्थिति बिन गई है। हालाँकि, यह वभिज्य पूल (divisible pool) के आकार को प्रभावित कर सकता है, जिससे राज्यों के बीच ववितरण के लिये उपलब्ध धनराशि पर असर पड़ सकता है। इससे संसाधन आवंटन और ववित्तीय स्वायत्तता में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है।

- उदाहरण के लिये, **जीएसटी कषतपिरत उपकर (GST compensation cess)** अपर्याप्त और असामयिक भुगतान के कारण प्रायः वविदों से रहा है।

■ **केंद्रीय वधिान:** केंद्रीय वधिान के कई खंड, जैसे **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005**, **नशुलक और अनविर्य बाल शक़िषा अधिकार अधिनियम 2009**, **राष्ट्रीय खाद्य सुरक़षा अधिनियम 2013** और कई अन्य अधिनियम राज्यों पर अतरिकित बोझ डालते हैं।

■ **उभरते राजनीतिक वमिरश:** भारत अब स्वातंत्र्योत्तर काल का एकदलीय शासन नहीं रह गया है। यह वास्तव में बहुदलीय वव्यवस्था में परणित हो चुका है। राजनीतिक प्रकृति, समाज, प्रौद्योगिकी, जनसांख्यिकीय संरचना और विकास परतमिन महत्त्वपूर्ण रूप से बदल गए हैं। इन परिवर्तनों के परणामस्वरूप, भारत का राजनीतिक कषेत्र अधिक परतसिपर्द्धी और गतशील हो गया है जिससे नए ववित्तीय आयाम खुले हैं।

भारत अपने राजकोषीय संघवाद को कैसे सुदृढ़ कर सकता है?

■ **समता-उन्मुख अंतर-सरकारी हस्तांतरण:** केंद्र सरकार से राज्यों को आवंटित धनराशि जैसे अंतर-सरकारी हस्तांतरण को इस तरह से अभकिलपति क़िया जाना चाहिये जो समता को बढ़ावा दे।

- **कषेतजि और ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन:** कषेतजि असंतुलन (वभिन्न राज्यों के बीच असमानताएँ) और ऊर्ध्वाधर असंतुलन (केंद्र और राज्य सरकारों के बीच), दोनों को ही संबोधित करना अत्यंत आवश्यक है। हस्तांतरण के फ़ॉर्मूले को इस प्रकार अभकिलपति क़िया जाना चाहिये कि यह दोनों प्रकार के असंतुलन पर ववचार करे ताकि संसाधनों का उचित आवंटन सुनिश्चित क़िया जा सके।

■ **प्रदर्शन-आधारित अनुदान:** प्रदर्शन-आधारित अनुदान (Performance-Based Grants) शुरु क़िये जाने चाहिये जो स्वास्थय और शक़िषा संकेतकों में सुधार जैसे कुछ वविकासात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये राज्यों को पुरस्कृत करते हों। यह राज्यों को प्रभावी शासन और परणामों पर ध्यान केंद्रित करने के लिये प्रोत्साहित करेगा।

■ **संवैधानिक सुधार:** केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों के वभिजन को पुनर्रभिषित करने के लिये **अनुच्छेद 246 और सातवीं अनुसूची** पर पुनर्रवचार करना प्रासंगिक होगा। इससे यह स्पष्ट करने में मदद मलित सकती है कि प्रत्येक स्तर पर कौन-से कार्य क़िये जाने चाहिये; इससे भ्रम कम होगा और दक़्षता बढ़ेगी।

■ **स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाना:** सरकार के इस तीसरे स्तर को पर्याप्त संसाधन, कार्य उत्तरदायित्व और स्वायत्तता प्रदान कर सशक्त बनाया जाना चाहिये। इसमें उत्तरदायित्वों और ववित्त के लिये एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार करना शामिल हो सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि स्थानीय नकियों के पास ऐसे नरिणय लेने की शक़त है जो उनके समुदायों को प्रभावित करते हैं।

■ **सार्वभौमिक ववित्तीय रपिोर्टगि प्रणाली:** एक मानकीकृत ववित्तीय रपिोर्टगि प्रणाली लागू की जानी चाहिये जो सरकार के सभी स्तरों को दायरे में लेती हो। इससे पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशल ववित्तीय प्रबंधन बनाए रखने में मदद मलित सकती है।

■ **ऑफ-बजट उधारी की समीक़षा करना:** यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी ववित्तीय लेनदेन बजट में शामिल हैं, ऑफ-बजट उधारी (Off-Budget Borrowing) के मुद्दे को संबोधित क़िया जाना चाहिये। इससे राजकोषीय प्रबंधन में प्रच्छन्न देनदारियों (hidden liabilities) पर रोक लगेगी और

पारदर्शिता बढ़ेगी।

- **विकास संकेतकों का अभिसरण:** धन के आवंटन में प्रतियोगिता आर्थिक और मानव विकास सूचकांक (HDI) जैसे आर्थिक एवं सामाजिक संकेतकों के संयोजन का उपयोग किया जाना चाहिये। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करेगा कि राज्य न केवल आर्थिक रूप से विकसित होंगे बल्कि अपने नागरिकों के समग्र कल्याण में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे।
- **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम:** केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिये FRBM अधिनियम के प्रावधानों को संरक्षित किया जाना चाहिये ताकि वे अपनी वशिष्ट राजकोषीय स्थितियों को समायोजित करते हुए राजकोषीय अनुशासन बनाए रखें।
- **कर शक्तियों का हस्तांतरण:** राज्यों को कराधान पर अधिक लचीलापन और नयित्त्रण प्रदान किया जाना चाहिये, जो उन्हें उनकी स्थानीय आर्थिक स्थितियों एवं प्राथमिकताओं के अनुसार राजस्व उत्पन्न करने में सक्षम बनाएगा।
- **सहकारी संघवाद:** सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा दिया जाए जहाँ केंद्र और राज्य सरकारें उन नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में सहयोग करेंगी जो समग्र रूप से पूरे देश को लाभ पहुँचाएँगी।
- **नियमिती समीक्षा और संवाद:** राजकोषीय मुद्दों, नीतित्त्रण चुनौतियों और राजकोषीय संघवाद ढाँचे में संभावित सुधारों पर चर्चा करने के लिये केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच नियमिती समीक्षा और संवाद के तंत्र स्थापित किये जाने चाहिये।

अभ्यास प्रश्न: हाल के घटनाक्रमों के आलोक में भारत के राजकोषीय संघवाद पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता का परीक्षण कीजिये। भारत में राजकोषीय संघवाद के सिद्धांतों और अभ्यासों में सुधार के लिये कुछ उपाय सुझाइये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्र. नमिनलखिती में से कौन सी भारतीय संघवाद की वशिषता नहीं है? (2017)

- (a) भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है।
- (b) शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से वभिजति किया गया है।
- (c) संघीय इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतनिधित्व दिया गया है।
- (d) यह संघीय इकाइयों के बीच एक समझौते का परिणाम है।

उत्तर: D

प्र. स्थानीय स्वशासन को किस एक अभ्यास के रूप में सबसे अच्छी तरह से समझाया जा सकता है? (2017)

- (a) संघवाद
- (b) लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
- (c) प्रशासनिक प्रतनिधिमिडल
- (d) प्रत्यक्ष लोकतंत्र

उत्तर: B

प्रश्न. नमिनलखिती पर वचिार कीजिये: (2018)

1. छलिका उतरे हुए अनाज
2. मुरगी के अंडे पकाए हुए
3. संसाधित और डबिबाबंद मछली
4. वजिापन सामग्री युक्त समाचार-पत्र

उपर्युतत में से कौन-सा/से जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवा कर) के अंतरगत छूट प्राप्त है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1, 2 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर : (c)

प्रश्न. 'वस्तु एवं सेवा कर (गुड्स एंड सर्वसिज़ टैक्स/GST)' के क्रियान्वति किये जाने का/के सर्वाधिक संभावित लाभ क्या है/हैं? (2017)

1. यह भारत में बहु-प्राधिकरणों द्वारा वसूल किये जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा और इस प्रकार एकल बाज़ार स्थापित करेगा।

2. यह भारत के 'चालू खाता घाटे' को प्रबलता से कम कर वदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने हेतु उसे सक्रम बनाएगा ।
3. यह भारत की अर्थव्यवस्था की संवृद्धि और आकार को बृहद् रूप से बढ़ाएगा तथा उसे नकित भवषिय में चीन से आगे नकिल जाने योग्य बनाएगा ।

नमिनलखिति कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/rethink-india-s-fiscal-federalism>

